

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014—भाद्र 14, शक 1936

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 27) राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सोलंकी, पिता श्री मनोज कुमार सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1978 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 06) राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह, पिता श्री गोविन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 11 मार्च 1978 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 14) राज्य शासन, सुश्री रानो पाल, पिता पहलवान सिंह पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है। उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1987 है।

## उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ 6-6-2014-58.—विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630 (3) के अनुक्रमांक-18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है।

यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 से ही लागू मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. 4540-5589-2013-आठ.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)-19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीलू मरकाम, अवर सचिव.

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ-3-42-2014-बत्तीस.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4476-5622-बत्तीस-1976, दिनांक 8 नवम्बर 1976 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के प्रावधान अंतर्गत झाबुआ निवेश क्षेत्र की सीमाएं का गठन किया गया था। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(2) क अन्तर्गत पूर्व गठित झाबुआ निवेश क्षेत्र में ग्राम मिण्डल, बाडकुओं एवं ग्राम रतनपुरा को सम्मिलित करते हुए, संशोधित निवेश क्षेत्र का गठन करता जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार हैं:—

### अनुसूची

#### झाबुआ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम मिण्डल, बाडकुओं, रतनपुरा, आम्बाखोदरा, बिलीडोज की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम बिलीडोज, नाचनखेड़ा, धरमपुरी, गडवाडा की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा, नाचनखेड़ा एवं धरमपुरी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-12-2013-छब्बीस-1.—राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के द्वारा “समग्र पुनर्वास नीति” का प्रारूप तैयार करने के लिये पांच सदस्यों को आयोग में सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

1. सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतः अवैतनिक होगी.
2. समस्त सदस्य “समग्र पुनर्वास नीति” का प्रारूप तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष के अधीन रह कर कार्य में सहयोग करेंगे.

3. सदस्यों को राज्य एवं राज्य के बाहर यात्रा हेतु राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी के समरूप यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जावेगा.

4. आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रारूप नीति की बैठकों में भाग लेने हेतु रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यात्रा की पात्रता होगी.

5. समग्र प्रारूप नीति तैयार करने के संबंध में बाहर से आने वाले सदस्यों को 1000/- रुपये बैठक हेतु मानदेय होगा.

6. राज्य सरकार लोकहित में बिना सूचना दिये कभी भी हटा सकेगी. परन्तु उन्हें उचित सूचना दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जावेगा या सदस्यों को 15 दिवस की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा.

(2) उपरोक्त व्यय मांग संख्या-34-मुख्य लेखा शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-समाज कल्याण-800 अन्य व्यय-7360-राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन-42-सहायक अनुदान-0101 राज्य आयोजना सामान्य-002-संधारण अनुदान मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(3) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.

क्र. एफ 1-12-2013-छब्बीस-1.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-21-2013-एक (1), दिनांक 20 सितम्बर 2013 द्वारा श्री नानक राम वाधवानी, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

राज्य शासन एतद्वारा उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

क्र.	सुविधा का नाम	देय सुविधाएं
(1)	(2)	(3)
1	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	10,000/- प्रतिमाह
2	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	वाहन	1
4	वाहन चालक	1
5	पेट्रोल सीमा	100 लीटर प्रतिमाह

(1)	(2)	(3)
6	यात्रा सुविधा	रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी
7	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
8	निजी स्टॉक	निज सहायक-एक (8,000/- प्रतिमाह) भृत्य-2 (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार).
9	दूरभाष	कार्यालय-एक, निवास-एक
10	दूरभाष व्यय सीमा	रुपये 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर).
11	किराये के आवास की सुविधा.	रुपये 15,000/- प्रतिमाह

नोट.—किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 100 लीटर के मान से होगी.

(3) उपरोक्त सेवा शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12-2014-नियम-चार, दिनांक 2 अगस्त 2014 के संदर्भित आदेशों में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे उपाध्यक्ष जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.

(4) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. 1833-1670-2014-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मई 2015 तक सात माह के लिए छूट

देता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल भारतीय, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ 1(ए) 266-86-ब-2-दो.—श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9, 10, 15, 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 251-88-ब-2-दो.—श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9, 10, 15, 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक पटेरिया भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. एफ 1(ए) 273-86-ब-2-दो.—श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक (शिका/माअआ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 25 जनवरी 2014 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश

वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, शासन

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

संशोधन

क्र. 5559-2908-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई, की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908-अका-विपप्र-2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, जिसमें ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री मोहित बुदास, सहायक कलेक्टर को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिसे अब संशोधित किया जाता है, श्री मोहित बुदास को उपरोक्त विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय)

जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2014

आदेश

क्र. स.शि.-2014-1168.—आयुक्त सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-सुसे-2010-600, दिनांक 28 सितम्बर 2011 तथा मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण 2 जुलाई 2009 माता पिता एवं वरिष्ठ

नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन एवं निगरानी वर्ष 2014-15 में 6 माह हेतु निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त से प्राप्त सुलह अधिकारियों के नाम अनुसार खण्ड स्तरीय सुलह अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है।

1. श्री निरजंन सिंह लोधी, एडवोकेट उपखण्ड, विदिशा.
2. श्री संजय प्रधान, एडवोकेट उपखण्ड, विदिशा.
3. सीमा सोलंकी, एडवोकेट उपखण्ड, विदिशा.
4. श्री ताराचंद्र भावसार, एडवोकेट उपखण्ड, बासौदा
5. श्री सुभाषचन्द्र ताम्रकार, एडवोकेट उपखण्ड, बासौदा
6. श्री मुकेश रघुवंशी, एडवोकेट उपखण्ड, बासौदा
7. श्री पुरुषोत्तम कुशवाह, उपखण्ड ग्यारसपुर.
8. श्री मुकेश सोनी, एडवोकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.
9. श्री राजीव कुमार जैन, एडवोकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.
10. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
11. श्री हरगोविंद धाकड़, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
12. श्री हुकुम चन्द्र भावसार, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
13. श्री नसीरअली एडवोकेट उपखण्ड, कुरवाई
14. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, एडवोकेट उपखण्ड, कुरवाई
15. श्री कमल कुमार पटेल, एडवोकेट उपखण्ड, कुरवाई
16. श्री रमेश गर्ग, एडवोकेट उपखण्ड, सिरोंज
17. श्री अशोक रावल, एडवोकेट उपखण्ड, सिरोंज
18. श्री उमेश वाली, एडवोकेट उपखण्ड, सिरोंज
19. श्री कृष्णमोहन पाराशर, एडवोकेट उपखण्ड, लटेरी
20. श्री सबीर अली खान, एडवोकेट उपखण्ड, लटेरी
21. श्री डी. पी. कटारिया, सहायक विस्तार अधिकारी उपखण्ड लटेरी.

उक्त गठित समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में खण्ड स्तर पर कार्य करेगी।

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

## मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (सी-2, साउथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

फा. क्र. 38-स्था.-राविसेप्रा-1375-2014.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 8-क (2) तथा सहपठित विनियम 3(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एतद्द्वारा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:—

### उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

- |  |       |
|--|-------|
| 1. श्री के. एल. जाटव, अधिवक्ता, जबलपुर   | सदस्य |
| 2. श्रीमती देविका सिंह, अधिवक्ता, जबलपुर | सदस्य |
| 3. श्री चम्पालाल यादव, अधिवक्ता, इन्दौर  | सदस्य |
| 4. श्री नवल गुप्ता, अधिवक्ता, ग्वालियर   | सदस्य |

No. 38-Estt-SLSA-2014.— In exercise of the powers conferred by Section 8-A(2) of Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 3 (5) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulation, 1997 the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates the following persons as members of the High Court Legal Services Committee for a period of two years with effect from the date of assuming charge:—

### HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Shri K. L. Jatav, Advocate, Jabalpur    | Member |
| 2. Smt. Devika Singh, Advocate, Jabalpur   | Member |
| 3. Shri Champalal Yadav, Advocate, Indore. | Member |
| 4. Shri Naval Gupta, Advocate, Gwalior     | Member |

दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

### सूचना

क्र. एफ. 1-9-2013-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील कोलार, बैरागढ़, गोविंदपुरा, महाराणाप्रताप नगर, तात्या टोपे नगर, शहर भोपाल एवं हुजूर जिला भोपाल सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील हुजूर जिला भोपाल की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शायी प्रस्तावित तहसील, जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम (3) में दर्शाया गया है, को कॉलम (4) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम (5) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित

रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

### अनुसूची

क्र. (1)	प्रस्तावित तहसील (2)	मुख्यालय (3)	वर्तमान तहसील (4)	परिवर्तन का स्वरूप (5)	सीमाएं (6)
1	कोलार	बैरागढ़ चिचली.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 42 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कोलार में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'बैरागढ़ चिचली' होगा.	पूर्व में—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर एवं तात्याटोपे नगर. दक्षिण में—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन.
2	बैरागढ़	बेहटा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं. 06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 37 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील बैरागढ़ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'बेहटा' होगा.	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल पश्चिम में—तहसील सीहोर जिला सीहोर. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील हुजूर (शेष भाग). दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
3	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 23 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील गोविंदपुरा में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'गोविंदपुरा' होगा.	पूर्व में—तहसील रायसेन जिला रायसेन पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल एवं प्रस्तावित तहसील हुजूर. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील हुजूर एवं तहसील रायसेन जिला रायसेन. दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.
4	महाराणा प्रताप नगर.	अहमदपुर कलां.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 39 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील महाराणा प्रताप नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'अहमदपुर कलां' होगा.	पूर्व में—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर एवं प्रस्तावित तहसील कोलार. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा. दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील कोलार.
5	तात्याटोपे नगर.	कोटरा सुल्तानाबाद.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 58 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील कोलार एवं प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर. पश्चिम में—तहसील सीहोर जिला सीहोर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				प्रस्तावित नवीन तहसील तात्याटोपे नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'कोटरा सुल्तानाबाद' होगा.	उत्तर में—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल. दक्षिण में—तहसील सीहोर जिला सीहोर.
6	शहर भोपाल.	कोहेफिजा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक कुल 16 पटवारी हल्के कुल इस प्रकार कुल 27 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील शहर भोपाल में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'कोहेफिजा' होगा.	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ उत्तर में—प्रस्तावित तहसील हुजूर दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
7	हुजूर	ईटखेड़ी सड़क	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं. 06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक, कुल 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक, कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 104 पटवारी हल्के जिनमें 226 राजस्व ग्राम हैं. अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील हुजूर में रा.नि.मं.-01 ईटखेड़ी के प.ह.नं. 1 से 14 तक तथा रा.नि.मं.-02 चोपड़ाकलां के प.ह.नं. 15 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के जिनमें 78 राजस्व ग्राम शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'ईटखेड़ी सड़क' होगा.	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में—तहसील श्यामपुर जिला सीहोर. उत्तर में—तहसील बैरसिया दक्षिण में—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं शहर भोपाल.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.



## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. 6724-भू-अर्जन-24-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—खिरकिया  
(ग) नगर/ग्राम—छीपाबड  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.755 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
83/1	0.153	सिंचित
84	0.174	असिंचित
89	0.425	सिंचित
14/2	0.113	सिंचित
18	0.109	सिंचित
4/2	0.101	सिंचित
129/1	0.045	असिंचित
83/2	0.008	सिंचित
85/1, 85/2	0.105	सिंचित
14/3	0.275	सिंचित
17	0.077	असिंचित
2	0.065	असिंचित
4/1	0.105	सिंचित

योग . . 1.755

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 1 एल माइनर एवं 2 एल माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6726-भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—खिरकिया  
(ग) नगर/ग्राम—चौकडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.025 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
161/1	0.045	असिंचित
715/1, 715/2	0.089	सिंचित
710/1	0.073	सिंचित
702/1, 702/2	0.073	असिंचित
705	0.065	असिंचित
699	0.032	असिंचित
694	0.089	सिंचित
681/4	0.016	सिंचित
210/1	0.234	असिंचित
212	0.024	असिंचित
689/2	0.185	असिंचित
237	0.045	असिंचित
667	0.032	असिंचित
668/1	0.032	सिंचित
661	0.012	सिंचित
654/1, 654/2	0.153	सिंचित
649/1	0.041	सिंचित
650	0.081	सिंचित
644	0.049	सिंचित
642	0.057	सिंचित
716	0.105	सिंचित
714/1, 714/2	0.093	सिंचित
710/2	0.097	सिंचित
704	0.081	सिंचित
706	0.049	असिंचित

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
695/1, 695/2, 695/3	0.206	असिंचित	281/3	0.101	सिंचित
681/3	0.097	असिंचित	288	0.101	सिंचित
207/3	0.032	असिंचित	292/1	0.250	सिंचित
211	0.061	असिंचित	290	0.113	सिंचित
219/1	0.145	सिंचित	291/4	0.053	सिंचित
236	0.012	असिंचित	योग . . 0.810		
238	0.032	असिंचित	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 3 एल माइनर निर्माण हेतु.		
668/2	0.065	असिंचित	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
662	0.121	असिंचित	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
660	0.162	सिंचित			
653	0.065	सिंचित			
651	0.057	सिंचित			
645	0.045	सिंचित			
643	0.061	सिंचित			
641/1	0.012	सिंचित			
योग . . 3.025					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 4 एल माइनर एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6728-भू-अर्जन-25-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—खिरकिया  
(ग) नगर/ग्राम—खिरकिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
280/1	0.020	सिंचित
281/1	0.172	असिंचित

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—दुधावरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.314 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	1.692 में से 0.314 हे. भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरतौली से डाबरी मार्ग निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—बाबईखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
19/2	0.460 हे. में से 0.180 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सनाई से दानखेडी मार्ग के निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—रमखिरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.120
05	0.130

(1)	(2)
01	0.202
16	0.050
17	0.050
योग . .	0.552

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की वितरिका नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—पठारी  
(ग) ग्राम—परसौरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.795 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
215/4क	0.283
217/2/1	0.043
217/2/2	0.109
217/2/3	0.305
217/2/4	0.030
217/2	0.305
217/3/1	0.120
217/5	0.600
योग . .	1.795

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्य सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—पठारी
- (ग) ग्राम—रामगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.986 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
23/2/1	0.400
23/4/1	0.664
23/9	0.341
23/10	0.341
23/11	0.341
23/12	0.341
23/6	0.500
23/7	0.500
25/2/2	0.800
40/1	1.045
40/2	0.418
40/3	0.836
40/4	0.627
63/3/1	1.412
41	0.420
योग . .	8.986

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. 468-भू-अर्जन-2014-प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) नगर/ग्राम—बन्नाखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
226/2	1.012
योग . .	1.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जावरा शहर के चौपाटी क्षेत्र में बस स्टेण्ड की स्थापना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 914-प्रका.-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) नगर/ग्राम—डिहली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.07 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

1223/1क	0.01
1223/1	0.06
योग (अ)	0.07

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कुस्परी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 916-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—मबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.350 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर के मबई माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

1983	0.040
1984	0.120
2051	0.110
2052	0.020
2045	0.020
1212	0.040
योग (अ)	0.350

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मबई माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 918-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट

- (ग) नगर/ग्राम—टीकट खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.04 हेक्टेयर.

- (ग) नगर/ग्राम—टटिहरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.412 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

122/1, 122/2, 122/3	0.040
योग (अ)	<u>0.040</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)	<u>0.04</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवाई माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. 922-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कचुलियान

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
294/1, 294/2	0.574
262	0.611
263	0.049
260	0.446
304	0.192
252	0.042
253	0.410
254	0.061
255	0.624
251	0.002
244	0.013
245	0.685
185/1, 185/2,	0.058
185/3, 185/4,	
185/5	
186/1, 186/2,	0.990
186/3, 186/4,	
186/5	
132	0.514
56/1, 56/2	0.269
130	0.007
129	0.004
63	0.041
64	0.509
62	0.041
68/1/क, 68/1ख, 68/2	0.310
61	0.042
60	0.010
72	0.615
73	0.047
74	0.081
75	0.020
76	0.014
191	0.041
267	0.004
निजी पट्टे की भूमि का योग	<u>7.326</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि		981	0.032
		985	0.015
125	0.012	984	0.002
303	0.040	988	0.063
184	0.034	972	0.007
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.086	993	0.082
(अ+ब) का योग . .	7.412	992	0.011
		980	0.027
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		989	0.067
		990	0.155
		991	0.106
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		1022	0.016
		1023	0.012
		1020	0.008
		1021	0.053
पत्र क्र. 924-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		1014	0.083
		1013	0.011
		1012	0.109
		1015	0.247
		1019	0.015
		1018	0.022
		1016	0.057
		1017	0.027
अनुसूची		900	0.076
(1) भूमि का वर्णन—		899	1.124
(क) जिला—रीवा		876/1, 876/2	0.127
(ख) तहसील—गुढ़		875	0.086
(ग) ग्राम—नरहा		874	0.022
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.312 हेक्टेयर.		864/1, 864/2/1, 864/2/2	0.033
खसरा नं.	अर्जित रकबा	863/1, 863/2	0.065
	(हेक्टेयर में)	818/1, 818/2	0.009
(1)	(2)	862/1, 862/2	0.001
अ—निजी पट्टे की भूमि		865	0.066
978	0.117	866/1	0.416
982	0.042	860/1, 860/2, 860/3	0.161
976	0.005	859/1	0.161
977	0.061	850	0.020
979	0.202	851	0.109

(1)	(2)
858/1, 858/2	0.094
852	0.061
848	0.183
853	0.066
842	0.173
839	0.200
838	0.033
836	0.129
1024	0.008
1026	0.001
861/1, 861/2, 861/3	0.003
847	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>5.082</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
878	0.192
941	0.038
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.230</u>
(अ+ब) का योग . .	<u>5.312</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 926-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—उलही कला 53  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.483 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

150/1, 150/2	0.058
152	0.511
153	0.278
201	0.073
200/1, 200/2	0.137
196	0.126
197	0.188
195	0.252
194	0.230
193	0.224
192/1, 192/2, 192/3,	0.560
192/4, 192/5	
189	0.013
188	0.023
190	0.024
191	0.195
233/1, 233/2, 233/3	0.240
232	0.007
231/1, 231/2, 231/3	0.936
253/1, 253/2, 253/3	0.036
254/1, 254/2, 254/3	0.905
255/1, 255/2, 255/3	0.032
256/1, 256/2	0.215
259	0.103
272	0.009
297/1, 297/2, 297/3	0.003
296/1, 296/2	0.007
295/1, 295/2, 295/3	0.232
275	0.324
274	0.123
279	0.030
278	0.013
276	0.544
394/1, 394/2, 394/3	1.110
391/1, 391/2, 391/3	0.117
395/1, 395/2	0.041
408/1, 408/2	0.200
409	0.483



(1)	(2)
415/1, 415/2, 415/3, 415/4 415/5	0.987
416/1, 416/2	0.073
417/1, 417/2	0.480
418	0.004
258	0.008
<b>अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .</b>	<b>10.154</b>

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

273, 273/1	0.254
410	0.034
151	0.036
396	0.005
<b>म. प्र. शासन की भूमि का योग . .</b>	<b>0.329</b>
<b>अ+ब का योग . .</b>	<b>10.483</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 928-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—उलही उन्मूलन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.793 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
<b>अ—नजी पट्टे की भूमि</b>	
55/1, 55/2, 55/3, 55/4	0.671
56	0.016

(1)	(2)
58/1, 58/2, 58/3	0.101
59/1, 59/2	0.391
60/1, 60/2, 60/3	0.495
61	0.468
62	0.221
42	0.005
41	0.625
15	0.089
16	0.009
18/1, 18/2	0.941
19/1, 19/2, 19/3	0.663
35, 35/2	0.017
20/1, 20/2	0.064
40/1, 40/2	0.017

**अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .** 4.793

**म. प्र. शासन की भूमि का योग . .** 0.000

**अ+ब का योग . .** 4.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 932-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—महगना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.155 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
<b>अ—नजी पट्टे की भूमि</b>	
362	0.022
363	0.033

(1)	(2)	(1)	(2)
364	0.180	27	0.004
365/1	0.045	24	0.166
365/2		23	0.033
360	0.051	17	0.345
367/1	0.329	18	0.416
367/2		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	7.099
368/1	0.053	ब. म. प्र. शासन की भूमि.	
368/2		359	0.056
369/1	0.300	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.056
369/2		अ+ब का योग . .	7.155
372	0.002		
401	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
373	0.769	मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस	
385	0.063	पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
374	0.004		
386	0.003	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं	
387	0.002	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया	
389	0.185	जा सकता है.	
384	0.083		
382	0.101		
381	0.236	पत्र क्र. 934-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को	
379	0.389	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
380	0.023	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
322/1	0.066	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
322/2		अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया	
321	0.460	जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन	
93	0.084	हेतु आवश्यकता है:—	
94	0.345		
95	0.266	अनुसूची	
106	0.007	(1) भूमि का वर्णन—	
62	0.001	(क) जिला—रीवा	
105	0.689	(ख) तहसील—मनगवां	
97	0.011	(ग) ग्राम—भीर	
100	0.082	(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.836 हेक्टेयर.	
99/1	0.010	खसरा नं.	अर्जित रकबा
99/2			(हे. में)
101	0.120	(1)	(2)
102	0.147		
116	0.057	अ—निजी पट्टे की भूमि	
103	0.023	327/1	0.192
115	0.213	327/2	
117	0.234	659	0.542
25	0.179	660	0.053
26	0.260	658/1	0.154

(1)	(2)
657/1	0.654
656/1	0.241
656/2	.
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	<u>1.836</u>
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>1.836</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 936-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—अतरारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.869 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

285/1	
285/2	
285/3	0.228
285/4	
285/5	
285/6	
280/1/1	
280/1/2	
280/2	

(1)	(2)
280/3	
280/4	0.813
280/5	.
280/6	
280/7	
273/1	
273/2	
273/3	0.456
273/4	
273/5	
274	0.282
272	0.035
271	0.116
268	0.109
270	0.004
267	0.015
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.058</u>
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
317	0.128
260	0.063
72	0.620
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.811</u>
अ+ब का योग . .	<u>2.869</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 938-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—टीकर		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —38.252 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा	2223/1	0.955
	(हे. में)	2223/2	
(1)	(2)	2232	0.307
		2233/1	0.405
		2233/2	
अ—निजी पट्टे की भूमि		3906/2/2230	
1680	0.597	3906/3/2230	
1677/1	0.337	3906/4/2230	
1677/2		3906/5/2230	0.008
1681	0.026	3906/6/2230	
1682	0.026	3906/7/2230	
1688	0.635	3906/2230	
1674/1		2235	0.943
1674/2		2236	0.073
1674/3	1.803	2237	0.117
1674/4		2231/1	
1674/5		2231/2	
1676/1	0.723	2231/3	
1676/2		2231/4	
1675	2.542	2231/5	
1813/1		2231/6	0.319
1813/2	0.061	2231/7	
1813/3		2231/8	
2229/1	1.781	2231/9	
2229/2		2231/10	
2093/1		2231/11	
2093/2	0.421	2231/12	
2093/3		3813/1	
2093/4		3813/2	
2094	0.657	3813/3	
2218	0.399	3813/4	
2216/1		3813/5	1.921
2216/2	0.074	3813/6	
2216/3		3813/7	
2216/4		3813/8	
2217/1		3813/9	
2217/2	0.257	3813/10	
2217/3		3813/11	
2217/4		3767	0.387
2215	0.149	3768	0.251
2220	0.030	3770/1	0.484
2221	0.491	3770/2	
2222	0.045	3756	0.348
3912/2215	0.214	3754	0.259

(1)	(2)	(1)	(2)
3755	0.073	3759/31	
3758/1		3759/32	
3758/2		3759/33	
3758/3		3759/34	
3758/4		3759/35	
3758/5		3759/36	
3758/6		3759/37	
3758/7	0.927	3759/38	
3758/8		3759/39	
3758/9		3759/40	
3758/10		3760/1	
3758/11		3760/2	
3758/12		3760/3	
3758/13		3760/4	
3759/1		3760/5	
3759/2		3760/6	0.150
3759/3		3760/7	
3759/4		3760/8	
3759/5		3760/9	
3759/6		3760/10	
3759/7		3760/11	
3759/8		3730/1	
3759/9		3730/2	
3759/10		3730/3	
3759/11		3730/4	
3759/12		3730/5	
3759/13		3730/6	2.952
3759/14	2.832	3730/7	
3759/15		3730/8	
3759/16		3730/9	
3759/17		3730/10	
3759/18		3869/3730	0.041
3759/19		3728	0.020
3759/20		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>25.040</u>
3759/21		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
3759/22			
3759/23		1842/1	0.145
3759/24		1842/2	
3759/25		2234	0.209
3759/26		3769	0.153
3759/27		1683	0.156
3759/28		1673	0.050
3759/29		1692	2.636
3759/30			

(1)	(2)	(1)	(2)
1695	6.420	137/1	
1694	1.211	137/2	0.091
1673	0.991	137/3	
3814	1.142	138/1	
3766	0.099	138/2	
योग . .	13.212	138/3	
अ+ब का योग . .	38.252	138/4	
		138/5	1.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		138/6	
		138/7	
		138/8	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		139/1	
		139/2	
		139/3	
		139/4	0.022
		139/5/1	
		139/5/2	
		139/5/3	
पत्र क्र. 940-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		141/1	
		141/2	
		141/3	
		141/4	0.194
		141/5/1	
		141/5/2	
		141/5/3	
		140	0.294
(1) भूमि का वर्णन—		25/1	
(क) जिला—रीवा		25/1/ग	
(ख) तहसील—गुढ़		25/1/घ	
(ग) ग्राम—खाम्हाडीह		25/1/ङ/1	0.080
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.340 हेक्टेयर.		25/1/ङ/2	
		25/2	
		25/3	
खसरा नं.	अर्जित रकबा	156/1	0.010
(1)	(हे. में)	156/2	
(2)		154	0.666
		159	0.068
अ—निजी पट्टे की भूमि		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.107
		म. प्र. शासन की भूमि	
131	0.064	127	0.083
129/1	0.134	152	0.097
129/2		72	0.053
130/1	0.289	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.233
130/2		अ+ब का योग . .	3.340
132	0.002		
135	0.052		
136	0.088		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 942-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.880 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1136/1 | 0.158

1136/2 |

1134/2 |

1134/3 |

1134/4 |

1134/5 | 0.841

1134/6 |

1134/7 |

1134/8 |

1133/2 |

1133/3 |

1133/4 |

1133/5 | 0.049

1133/1/क |

1133/1/ख |

1133/1/ग |

1132/1 |

1132/2 | 0.039

1132/3 |

(1)

(2)

1131

0.124

1146/1 |

0.050

1146/2 |

1145/1 |

1145/2 |

0.218

1129

0.059

1147

0.102

1148

0.002

1128/1 |

1128/1/1 |

1128/2/क |

1128/2/ख |

0.345

1128/2

1128/3 |

1150

0.040

1149/1 |

1149/2 |

1149/3 |

1151

0.032

1152/1 |

1152/2 |

0.072

1156

0.059

1154

0.003

1155

0.100

1170

0.077

1171

0.025

1169

0.178

1174

0.026

1166/1/1 |

1166/1/2 |

1166/2 |

1175/1 |

1175/2 |

1175/3 |

1175/3/1 |

1175/4 |

1185

0.577

1186/1 |

1186/2 |

1187

0.020

1188

0.002

1189

0.024

1190

0.030

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1191/1			
1191/2	0.151		
1191/3			
1191/4			
1193/1	0.186		
1193/2			
1193/3			
1192/1	0.049		
1192/2			
1215/1			
1215/2	0.197		
1215/3			
1215/4			
1212	0.007		
1213	0.216		
1214/1	0.274		
1214/2			
1226	0.002		
1225/1			
1225/2	0.435		
1225/3			
1222/1		खसरा नं.	अर्जित रकबा
1222/2	0.806		(हे. में)
1222/3		(1)	(2)
1224	0.008		
1228	0.024		
1229	0.024		
1255	0.031		
1254	0.078		
1245	0.085		
1246	0.003		
1247	0.450		
1252	0.032		
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	6.508	अ—निजी पट्टे की भूमि	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		79/1	
914	0.073	79/2	
1244	0.004	79/3/क	0.886
1253	0.190	79/3/ख	
1251	0.105	79/3/ग	
ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.372	79/4	
अ+ब का योग . .	6.880	78/1	
		78/2	
		78/3	0.338
		78/4	
		78/5	
		77/1	
		77/2	0.164
		77/3	
		94	0.297
		95	0.001
		93	0.186
		137	0.270



(1)	(2)
136	0.127
103	0.086
135	0.065
138	0.113
134	0.028
130/1	0.084
130/2	
131	0.138
132	0.077
128	0.061
129	0.022
127	0.273
125	0.038
126	0.023
124/1	
124/2	0.550
124/3	
120/1	0.004
120/2	
121/1	
121/2	0.001
121/3	
192/1	0.159
192/2	
123/1	
123/2	0.137
123/3	
117/1/क	
117/1/ख	0.014
117/1/ग	
117/2	
193/1	0.749
193/2	
208/1	0.212
208/2	
197	0.011
199	0.115
200	0.021
201	0.141
204	0.182
203	0.048
202	0.230
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.851</u>

(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
81	0.590
198	0.044
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	<u>0.634</u>
अ+ब का योग . .	<u>6.485</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 920-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—शकुलगवां  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.832 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

171/1	
171/2	0.461
171/3	
172	0.016
168/1	0.188
168/2	
170/1	0.030
170/2	
169/1	0.586
169/2	

(1)	(2)	(1)	(2)
164/1	0.015	ब—म. प्र. शासन की भूमि	0.000
164/2		ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग .	0.000
167/1	0.002	अ+ब का योग . .	3.832
167/2			
163/1	0.062	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “बहुती मुख्य सिंचाई परियोजना” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
163/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
162	0.040		
161	0.010		
121	0.626		
124	0.100		
125	0.052		
132	0.060		
134	0.070		
126/1	0.076	पत्र क्र. 930-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
126/2		अनुसूची	
127/1	0.197	(1) भूमि का वर्णन—	
127/2		(क) जिला—रीवा	
130	0.029	(ख) तहसील—गुढ़	
129	0.024	(ग) ग्राम—लढ़	
128	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.541 हेक्टेयर.	
131	0.028		
67	0.137	खसरा नं.	अर्जित रकबा
65	0.078		(हे. में)
66	0.024	(1)	(2)
59/1	0.021	अ—निजी पट्टे की भूमि	
59/2			
60	0.077	605	0.724
61	0.057	604	0.023
64	0.010	603/1	
58	0.046	603/2	0.595
62	0.045	603/3	
63	0.025	602/1	0.108
57	0.122	602/2	
56	0.036	601/1/क	
55	0.028	601/1/ख	0.350
54	0.007	601/2/1	
74/1, 74/2	0.221	601/2/2	
75	0.107		
76	0.097		
166/1	0.002		
166/2			
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.832		

(1)	(2)	(1)	(2)
600	0.305	523	0.091
599	0.201	479/1	
598	0.235	479/2	0.969
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.541	479/3	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		478/1	
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.000	478/2	0.683
अ+ब का योग . .	2.541	478/3	
		478/4	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		446/1	0.082
		446/2	
		445	0.644
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		444	0.035
		441/1	0.600
		441/2	
		437	0.006
		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.385

पत्र क्र. 946-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—शिवपुरवा रानी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.179 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1173/1	
1173/2	0.348
1173/3	
1173/4	
526/1	0.052
526/2	
525	0.271
524/1	0.604
524/2	

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

520	0.025
521	1.385
677	0.363
678	0.070
679	0.373
680	0.661
681	7.073
1175/1	1.818
1175/2	
440	0.026

ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	11.794
अ+ब का योग . .	16.179

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 948-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—गहिरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.192 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1037/1

1037/2

1037/3

1045/1

1045/2

1045/3

1039/1

1039/2

1039/3

1044/1

1044/2

1044/3

1046/1

1046/2

1046/3

1047/1

1047/2

1047/3

1048/1

1048/2

1048/3

1066/1

1066/2

1066/3

1066/4

1070/1

1070/2

1070/3

1070/4

0.147

0.026

0.002

0.024

0.094

0.045

0.067

0.019

0.149

(1)

(2)

1069/1

1069/2

1069/3

1069/4

1067/1

1067/2

1067/3

1067/4

1068/1

1068/2

1068/3

1068/4

1076/1/क

1076/1/ख

1076/2

1076/3/ग

1076/4/घ

1089/1

1089/2

1090/1

1090/2

1090/3

1091/1

1094/1

1094/2

1093

1092/2

1092

1083

0.143

0.146

0.045

0.554

0.256

0.193

0.396

0.465

0.269

0.029

0.003

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.072

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1038

1060

0.053

0.067

ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.120

अ+ब का योग . .

3.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 950-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सहिजना

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.608 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

624/2

624/3

624/4

624/5

624/5/1

624/6

624/7

624/8

624/9

624/10

624/11

624/12

624/13

624/14

624/15

624/16

624/17

624/18

624/19

624/20

624/21

624/22

624/23

624/24

624/25

624/26

624/27

624/28

624/29

624/30

1.578

(1)

(2)

624/31

624/32

624/33

624/34

624/35

624/36

624/37

624/38

624/39

624/40

624/41

624/42

624/43

624/44

624/45

624/46

624/47

624/48

624/49

624/50

624/51

624/53

624/54

624/1

624/52

624/55

623

0.264

589

0.003

584/4, 584

1.214

579

0.179

576/1, 576/1/ग

576/2, 576/3, 576/4

0.132

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.370

ब—म. प्र. शासन की भूमि

621

0.217

622

0.090

625

0.931

ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 1.238

अ+ब का योग . .

4.608

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 952-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—शिवपुरवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.058 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1071 1.523

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.523

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

1087 1.005

1090 0.530

ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 1.535

अ+ब का योग . . 3.058

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 954-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—गुढ़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1142 0.012

1143/1/क

1143/1/क/1

1143/1/क/2

1143/1/ख

1143/2/क

1143/2/ख

1143/3

1143/4/क

0.579

1143/4/ख

1143/5/क

1143/5/ख

1143/6/क

1143/6/ख

1143/7

1143/8

1143/9

1143/10

1143/11

1143/12

1143/13

1143/14

1143/15

1143/16

1685

0.156

1684

0.462

1683

0.049

1670/1

0.470

1670/2

1677

0.277

1678

0.008

1676

0.002

1671

0.094

1663/1

0.044

1663/2

1662/1

0.231

1662/2

(1)	(2)	(1)	(2)
1664	0.083	1653/5	
1665/1	0.005	1653/6	
1665/2		1653/7	
1661/1/क		1653/8	
1661/1/ख	0.154	1653/9	
1661/1/ग		1652/1	
1661/1/घ		1652/2	
1661/2		1652/3	
1661/3		1652/4	
1659/1		1652/5	
1659/2		1652/6	0.560
1659/3		1652/7	
1659/4	0.144	1652/8	
1659/5		1652/9	
1659/6		1652/10	
1659/7		1652/11	
1655/1		1652/12	
1655/2/क		1630/1	0.298
1655/2/ख		1630/2	
1655/3/क		1626/1	0.113
1655/3/ख		1626/2	
1655/3/ग	0.073	1629/1	0.061
1655/3/घ		1626/2	
1655/3/ङ		योग . .	<u>4.209</u>
1655/3/च		<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
1655/3/छ			
1655/4		1628	0.073
1660/1	0.147	योग . .	<u>0.073</u>
1660/2		अ+ब का योग . .	<u>4.282</u>
1650/1			
1650/2		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
1650/3			
1650/4			
1650/5			
1650/6	0.164	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1650/7			
1650/8			
1650/9			
1650/10			
1650/11			
1653/1			
1653/2			
1653/3			
1653/4	0.023		

क्र. 956-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—पांती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.417 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1102/1	
1102/2	0.942
1102/4	
1102/5	
1127/1	
1127/2	0.909
1127/3	
1127/4	
942	0.695
929	0.475
941	0.001
930	0.161
926	0.100
925	0.075
922	0.007
920	0.169
919	0.026
918	0.028
917	0.092
913/1	
913/2/क	0.010
913/2/ख	
916/2	0.786
916/1	

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . . 4.476

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

924	0.365
1131	0.483
915	0.093

ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.941

अ+ब का योग . . 5.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 958-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़  
(ग) ग्राम—हर्दी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.215 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1100	0.020
1102/1	
1102/2	
1102/3	0.367
1102/4	
1102/5	
1101	0.014
1105	0.003
1106/1	0.050
1106/2	
1099/1	0.386
1099/2	
1083	0.120
1084	0.136
1085/1	
1085/2	0.307
1085/3	
1085/4	
1081/1	
1081/2	0.002



(1)	(2)	(1)	(2)
1080	0.002	899	0.015
1087	0.010	898	0.070
1088	0.071	897	0.184
1090/1		497/1	
1090/2	0.001	497/2	0.226
1090/3		497/3/1	
1090/4		497/3/2	
950	0.600	497/4	
943	0.117	503/1	
949/1		503/2	
949/2	0.194	503/3/1	0.077
949/3		503/3/2	
944	0.097	503/4	
948	0.005	502/1	
946	0.028	502/2	
945/1	0.186	502/3/1	0.259
945/2		502/3/2	
942	0.123	502/4	
941	0.046	501/1	
940	0.389	501/2	
939	0.107	501/3/1	0.151
974	0.034	501/3/2	
975	0.064	501/4	
981	0.102	500/1	0.079
923	0.073	500/2	
924/1	0.026	499/1	0.016
924/2		499/2	0.012
925	0.070	499/3	0.012
922	0.469	499/4	0.016
918/1		498/1	
918/2	0.154	498/2	
918/3		498/3	0.318
917/1	0.202	498/4	
917/2		429/1	
916/1		429/2	
916/2		429/3/1/क	
916/3	0.222	429/3/1/ख	0.531
916/4		429/3/2/क	
909	0.268	429/3/2/ख	
911/1		429/4	
911/2	0.171	429/5	
910	0.032	429/7	
901	0.039	428	0.024
900/1		426	0.266
900/2	0.506	427	0.152
900/3			
9004			

(1)	(2)
432	0.039
433	0.100
434	0.243
438	0.060
440	0.011
437	0.039
436	0.022
439/1	0.408
439/2	
450	0.067
451	0.073
452/1/क	
452/1/ख	0.033
452/2	
453	0.380
457/1	
457/2	0.501
457/6	
462	0.019
463	0.012
464	0.003
461	0.010
458	0.070
460	0.280
1079	0.282
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>10.873</u>

## ब—म. प्र. शासन की भूमि

394	0.086
454	0.024
455	0.103
459/1	0.748
459/2	
921	0.025
1089	0.053
1097	0.045
1111	0.092
1129	0.137
920	0.029
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग .	<u>1.342</u>
अ+ब का योग . .	<u>12.215</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 960-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—मड़वा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.666 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

## अ—निजी पट्टे की भूमि

1495/1/1	
1495/1/2	
1495/1/3	
1495/1/4	0.830
1495/1/5	
1495/1/6	
1495/2	
1580	0.265
1578/1	
1578/1/क	
1578/1/ख	0.682
1578/2	
1578/3	
1578/4	
1576/1	
1576/2	0.760
1576/3	
1722	0.455
2297/1720	0.255
1724/1	0.066
1724/2	

(1)	(2)	(1)	(2)
1737	0.483	2101	0.067
1738	0.174	2102	0.247
1739	0.765	2100	0.212
1733/1	0.104	2089/1	0.043
1733/2		2089/2	
1731	0.027	2087	0.091
1740	0.295	2098	0.310
1741	0.307	2096	0.343
1742	0.045	2095	0.202
1743	0.253	2093	0.516
2065	0.162	2094	0.001
1744	0.211	2151	0.005
1749	0.107	2152	0.324
2034/1	0.390	2153	0.273
2034/2		2156	0.250
2033	0.299	2157	0.002
2119/1		2171	0.988
2119/2		2170	0.024
2119/3	0.781	2172	0.264
2119/4		2174/1	
2119/5		2174/2	0.009
2119/6		2174/3	
2120	0.016	1551/1	0.011
2111/1		1551/2	
2111/2		2035/1	0.232
2111/3	0.492	2035/2	
2111/4		2036/1	0.108
2111/5		2036/2	
2111/6		2037	0.034
2106/1/क		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . . 13.383	
2106/1/ख		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
2106/1/ग		1574	0.094
2106/1/घ		2135	0.113
2106/1/ङ		2173	0.076
2106/1/च	0.563	ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.283	
2106/1/छ		अ+ब का योग . . 13.666	
2106/1/ज		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
2106/1/झ		मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस	
2106/1/ञ		पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
2106/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं	
2105/1		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया	
2105/2	0.040	जा सकता है.	
2105/3			
2105/4			

क्र. 962-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) ग्राम—बांसा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.843 हेक्टेयर.

खसरा नं.                      अर्जित रकबा  
(हे. में)  
(1)                              (2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

1745	1.049
1627/1	
1627/2	0.186
1627/3	
1627/4	
1626	1.182
1625/1	
1625/2	0.036
1625/3	
1624/1	
1624/2	0.372
1624/3	
1749/1	
1749/2	0.052
1749/3	
1750	
1750/2	0.005
1750/3	
1751	
1751/2	0.147
1751/3	
1752	
1752/2	0.019
1752/3	

(1)	(2)
1753/1	
1753/2	0.054
1753/3	
1754/1	
1754/2	0.271
1754/3	
1755/1	
1755/2	0.462
1755/3	
1755/4	
1756/1	
1756/2	
1756/3	
1756/4	0.453
1756/5	
1756/6	
1756/7	
1781	0.192
1982	0.361
1786	0.081
1744	0.366
1785/1	0.265
1785/2	
1787/1	
1787/2	0.565
1787/3	
1787/4	
1156/1	
1156/2/1	
1156/2/2	
1156/2/3	0.508
1156/2/क	
1156/3	
1156/4	
1154	0.181
1153	0.027
1150/1	0.159
1150/2	
1170/1	
1170/2/1	
1170/2/2	0.404
1170/2/3	
1171/1	0.333
1171/2	

(1)	(2)	(1)	(2)
1136	0.691	878	0.006
1139	0.064	882/1	0.002
1131/2		882/2	
1131/3	0.164	881	0.126
1131/4		880	0.137
1135	0.086	873/1	0.047
1134	0.082	873/2	
1133	0.274	873/3	
1108/1	0.580	886	0.149
1108/2		885	0.080
1107	0.046	888/1	0.056
1109/1	0.045	888/2	
1109/2		1774	0.366
942	0.026	1784	0.003
940	0.048	1097	0.419
939	0.234	941	0.005
937	0.068	<b>अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..</b>	
936	0.036		<u>13.697</u>
944	0.129	<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
950/1	0.003	1780	0.044
950/2		1742	0.047
952/1		1741	0.055
952/2/1		<b>ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .</b>	
952/2/2	0.458		<u>0.146</u>
952/3		<b>अ+ब का योग . .</b>	
952/4			<u>13.843</u>
951/1	0.012	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
951/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
953/1	0.098	प. क्र. 964-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
953/2		<b>अनुसूची</b>	
953/3		(1) भूमि का वर्णन—	
903/1		(क) जिला—रीवा	
903/2	0.073	(ख) तहसील—गुढ़	
903/3			
903/4			
857/1			
857/1/क	0.386		
857/1/ख			
857/2			
857/3			
857/4			
901	0.330		
899	0.592		
879	0.046		

(ग) ग्राम—बरसैता		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.973 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	228/1	0.234
(1)	(2)	228/2	
		229	0.028
		230	0.034
		231	0.073
		232	0.053
		233	0.029
		234	0.025
		235/1	0.010
		235/2	
		237	0.007
		238	0.045
		239	0.050
		240	0.120
		241	0.022
		261	0.213
		262	0.107
		263	0.008
		289	0.206
		292/1	
		292/2	0.012
		292/3	
		293/1	
		293/2	0.293
		293/3	
		294/1/1/1	
		294/1/1	0.023
		294/1/2	
		294/2	
		295	0.047
		426	0.011
		428	0.180
		429	0.107
		430	0.008
		431	0.035
		486	0.065
		487	0.009
		488	0.069
		489	0.052
		490/1	0.008
		490/2	
		491/1	
		491/1/1	0.153
		491/2	
176/1	0.062		
176/2			
177/1			
177/2	0.023		
177/3			
183/1	0.032		
183/2	0.029		
184	0.057		
185	0.016		
186/1	0.041		
186/2			
188	0.077		
190	0.010		
191/1	0.048		
191/2	0.049		
192	0.027		
196/1/1	0.527		
196/1/2			
196/2			
197	0.030		
198	0.034		
199	0.077		
200	0.043		
205	0.027		
206	0.066		
207/1	0.038		
207/2			
208	0.032		
209	0.033		
211	0.083		
212	0.030		
213	0.058		
214/1	0.017		
214/2			
225/1	0.003		
225/2			
227	0.059		

## अ—निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)	(1)	(2)
493	0.083	566/1	0.054
494/1	0.140	566/2	
494/2	.	187/1	0.103
495	0.036	187/2	
496	0.133	अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.. <u>5.947</u>	
497/1	0.033	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
498	0.005	290	0.026
562	0.025	ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. . <u>0.026</u>	
563	0.024	अ+ब का योग . . <u>5.973</u>	
564	0.002	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
565/1	0.066	मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस	
565/2		पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
567/1	0.007	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं	
567/2		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया	
568	0.036	जा सकता है.	
569	0.146	रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2014	
570	0.038	प. क्र. 970-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को	
572	0.028	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
573/1	0.008	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
573/2	0.020	की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
573/3	0.016	अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित	
573/4	0.008	किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के	
573/5	0.012	अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
573/6	0.008	अनुसूची	
574	0.008	(1) भूमि का वर्णन—	
575	0.042	(क) जिला—रीवा	
576	0.066	(ख) तहसील—गुढ़	
577	0.059	(ग) ग्राम—बदवार	
581	0.014	(घ) लगभग क्षेत्रफल —18.586 हेक्टेयर.	
582	0.097	खसरा नं.	
583	0.032	अर्जित रकबा	
584	0.057	(हे. में)	
585	0.029	(1)	
593/1	0.139	(2)	
593/2		अ—निजी पट्टे की भूमि	
594	0.042	5224/1	0.049
595/1	0.045	5224/2	
595/2		5223	0.014
596	0.043	5225	0.038
597/1	0.014	5226	0.245
597/2		5227	0.262
598	0.221		
599	0.025		
600	0.019		

(1)	(2)	(1)	(2)
5220	0.003	5315	0.023
5228/1		5279	0.038
5228/2	0.138	5280/1	
5228/3		5280/2	0.004
5247/1	0.197	5280/3	
5247/2		5280/4	
5245	0.012	5312	0.035
5248/1	0.092	5313	0.144
5248/2		5318	0.053
5246	0.080	5317	0.041
5250	0.120	5322/1	0.091
5255	0.036	5322/2	
5254	0.043	5320/1	0.318
5253	0.083	5320/2	
5256/1		5319	0.050
5256/2	0.237	5321/1	
5256/3		5321/2	0.165
5252	0.016	5321/3	
5170/1		5222	0.066
5170/2	0.024	5353/1	0.028
5170/3		5353/2	0.024
5258/1	0.002	5325/1	
5258/2		5325/2	0.405
5257/1	0.038	5325/3	
5257/2		5324	0.099
5267/1	0.123	5540	0.015
5267/2		5556	0.040
5264/1		5578	0.025
5264/2	0.025	5579	0.212
5264/3		5569	0.552
5265/1		5570	0.010
5265/2	0.024	5568	0.056
5265/3		5567	0.077
5266	0.139	5571	0.080
5277	0.271	5564	0.020
5276	0.042	5565	0.035
5275/1	0.260	5566	0.032
5275/2		5561	0.015
5278	0.006	5562	0.007
5274/1	0.026	5560	0.025
5274/2		5557	0.049
5273/1	0.058	5559	0.028
5273/2		5553	0.012
5314	0.089	5554	0.066



(1)	(2)	(1)	(2)
5555	0.029	4582/1	
5558	0.036	4582/2	
5552	0.028	4582/3	0.053
5436	0.002	4582/4	
5437	0.006	4582/5	
5543/1		4583/1	
5543/2	0.007	4583/2	0.120
5543/3		4583/3	
5542	0.026	5484	0.244
5541	0.053	4585	0.022
5438	0.036	4506	0.157
5441	0.015	4586	0.016
5440	0.040	4505	0.020
5439	0.032	4507	0.036
5452	0.037	4503	0.040
5466	0.051	4504	0.019
5467	0.045	4500	0.039
5462	0.011	4501	0.298
5464	0.002	4502	0.015
5465/1		4509	0.001
5465/2		4512	0.432
5465/3	0.015	4513	0.085
5465/4		4514/1	
5465/5		4514/2	0.123
5463/1		4514/3	
5463/2	0.213	4514/4	
5463/3		4515/1	0.151
5463/4		4515/2	
5454	0.019	4516	0.036
5455	0.142	4517	0.019
5456	0.009	4534	0.019
5450	0.017	4535	0.014
5451	0.053	4536/1	
5453	0.002	4536/2	0.028
4644	0.044	4536/3	
4631	0.081	4537	0.036
4630	0.042	4538/1	
4629	0.004	4538/2	0.062
4643	0.004	4538/3	
4632	0.048	4539	0.002
4633	0.045	4295/1	
4626	0.098	4295/2	0.486
4634	0.019	4295/3	
4635	0.027	4295/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
4296	0.012	2968	0.061
4297	0.072	2967	0.002
4298	0.020	2977	0.086
4299	0.008	2966	0.002
4294	0.059	3057	0.004
4300/1	0.040	3058	0.028
4300/2		3059	0.289
4293	0.207	3074/1	0.030
4182	0.022	3074/2	
4194	0.012	3063	0.014
4196	0.020	3064	0.040
4195	0.010	3071	0.065
4197	0.015	3072	0.026
4201	0.020	3073	0.128
4198	0.101	3080	0.041
4290	0.037	3081	0.069
4289	0.032	3068	0.001
4287	0.028	3069	0.067
4288	0.032	3070	0.012
4199/1	0.010	3170	0.085
4199/2	0.030	3171	0.087
4200	0.027	3082	0.025
4205	0.009	3079	0.002
4284/1	0.154	3083	0.019
4284/2		3168	0.038
4285	0.018	3169	0.042
4286	0.003	3172	0.047
2961	0.053	3176	0.024
4283	0.084	3177	0.013
4282	0.068	3173	0.045
4280	0.045	3174	0.057
4281	0.037	3167	0.056
2962	0.109	3175	0.061
2960	0.058	3180	0.001
4261	0.016	3182	0.047
4262/1	0.039	3181	0.016
4262/2		3161	0.025
2963	0.069	3162	0.069
2964	0.040	3163	0.105
2959	0.012	3164	0.014
2965	0.073	3165	0.023
2969	0.087	3155	0.047
2970/1	0.041	3183	0.109
2970/2		3184	0.001
2971	0.015		

(1)	(2)	(1)	(2)
3153	0.026	3441	0.004
3154	0.085	1112	0.045
3130	0.005	1111	0.073
3131	0.101	1125	0.022
3132	0.081	1109	0.091
3133	0.008	1110	0.021
3147	0.021	1126	0.053
3148	0.006	1124	0.004
3141	0.020	1127	0.124
3142	0.050	1128	0.001
3143	0.024	1105	0.033
3144	0.009	1129	0.058
3134	0.013	1100	0.049
3140/1	0.090	1101	0.049
3140/2		1102	0.062
3135/1	0.002	1103	0.003
3135/2		1104	0.035
3137	0.078	1130	0.018
3138	0.068	1087	0.014
3139	0.002	1088	0.036
3136/1	0.079	1064	0.095
3136/2		1065	0.018
2808	0.009	1099	0.019
2807/1	0.093	1089	0.011
2807/2		1090	0.016
3401	0.003	1091	0.020
3405	0.017	1061	0.005
3406	0.036	1063	0.150
3407	0.039	1163	0.054
3408	0.082	1167	0.026
2806	0.019	1164	0.004
3415	0.104	1166	0.015
3416	0.027	1168	0.098
3417	0.004	1169	0.035
3433	0.010	1175	0.124
3434	0.027	1174	0.052
3412	0.082	1176	0.040
3413	0.012	1173	0.080
3414	0.053	1183	0.021

(1)	(2)
1184	0.107
1185	0.043
1194	0.087
1195	0.025
1187	0.107
1188	0.096
1189	0.096
1190	0.014
1193	0.011
817	0.140
818	0.117
819/1	0.052
819/2	
813	0.002
810	0.073
811	0.024
826/1	
826/2	0.071
826/3	
809	0.088
827	0.063
796	0.101
798	0.279
786/1	0.079
786/2	
787	0.081
1186	0.003
921	0.003
820/1	0.009
820/2	
795	0.082
838	0.048
793	0.008
794	0.048
791	0.006
784	0.001
785	0.025
782	0.005
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..	18.567
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
4291	0.019
म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.019
अ+ब का योग . .	18.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 972-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—पतेला गुड़िया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.234 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

### अ—निजी पट्टे की भूमि

28	0.092
26	0.134
25	0.008

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.. 0.234

### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.000
अ+ब का योग . .	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 974-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—पटपरा

(घ) क्षेत्रफल —6.043 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

17/2

17/3

17/4

17/5

17/6

17/1

266/1/क/2

266/1/क/4

266/1/क/5

266/1/क/6

266/2/क

266/1/क/1

266/1/क/3

266/3

266/4

266/5

266/1/ख

266/6

266/2/ग

266/2/ख

258/1

258/3

258/2

257/1, 257/2

256/2

256/3

256/1/क/2/ख

256/1/घ

0.100

0.097

0.674

0.304

1.057

(1)

(2)

256/1/ख

256/1/क/2

256/1/क/3

256/1/क/1/ख

256/1/क/4

256/1/क/1/क

256/1/ग

20

21

22/1

22/2

23/1

23/2

25/1

25/2

25/3

26/2

26/1

27/1

27/2

27/3

27/4

27/5

27/6

28

29

30/1

30/2

33/1/क

33/1/ख

33/1/ग

33/1/घ

33/2/क

33/2/ख

33/2/ग

33/3

33/4

33/5

33/6

33/7

34

36

0.921

0.123

0.083

0.083

0.440

0.041

0.374

0.234

0.244

0.227

0.542

0.168

0.024

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 5.736

(1)	(2)	(1)	(2)
<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>		126/3	
35	0.016	126/2	
37	0.117	126/1	0.172
16	0.174	126/5	
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.307		126/4	
अ+ब का योग : 6.043		926/124	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		124	0.158
		925/123	0.032
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		123/3	
		123/1	0.170
		123/2	
		111/2	
		111/1	0.083
		112/2	
		112/1	0.240
		112/3	
		110/1	0.278
		110/2	
क्र. 976-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		109/1/क	
		109/1/ख	0.170
		109/2	
		108/1/ख	
		108/2	0.185
		108/1/क	
<b>अनुसूची</b>		42/3	
(1) भूमि का वर्णन—		42/4	
(क) जिला—रीवा		42/1	0.625
(ख) तहसील—मऊगंज		42/2	
(ग) ग्राम—सगरा		38	0.292
(घ) क्षेत्रफल —5.132 हेक्टेयर.		39/2	
खसरा नं.	अर्जित रकबा	39/1/ख	0.515
	(हे. में)	39/3	
(1)	(2)	39/1/क	
<b>अ—निजी पट्टे की भूमि</b>		40/1/ख	
170/1	0.038	40/3/ख	
170/2		40/3/ग	
940/1/170	0.004	40/2	0.561
940/2/170		40/5	
936/164	0.024	40/4	
164	0.044	40/1/क	
935/1/क/163		40/6	
935/2/163	0.020	11	0.088
935/1/ख/163		9	0.214
163/1	0.061		
163/2			
927/2/136			
927/1/136	0.040		

(1)	(2)
8/1/क/1	
8/1/क/2	
8/1/क/3	0.160
8/1/क/4	
8/2	
13/4	
13/2	
13/3	0.028
13/1/ख	
13/1/क	
14/5	
14/1/ख	
14/4	0.326
14/1/क	
14/2	
14/3	
15	0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.555

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

6/1	0.373
6/2	
206	0.204

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.577

अ+ब का योग : 5.132

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 978-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—गुढ़

- (ग) ग्राम—रेरूआ  
(घ) क्षेत्रफल —1.692 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

**अ—निजी पट्टे की भूमि**

442/1, 442/2	0.010
440	0.018
439/1/1, 439/1/2	0.049
438	0.076
437	0.085
419	0.084
418	0.056
417	0.048
414/1, 414/2	0.079
413	0.306
412	0.065
410/1, 410/2	0.413
411	0.067
386	0.207
385	0.139

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.692

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 1.692

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 980-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पतेला तिवारी

(घ) क्षेत्रफल —2.144 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ—निजी पट्टे की भूमि

80/1, 80/2	0.335
------------	-------

78	0.031
----	-------

76/1

76/2

76/3

76/4	0.532
------	-------

76/5

76/6

77/1

77/2

77/3	0.040
------	-------

77/4

77/5

57	0.092
----	-------

58	0.137
----	-------

59/1, 59/2	0.083
------------	-------

60/1, 60/2	0.180
------------	-------

51/1/क, 51/1/ख, 51/1/ग	0.032
------------------------	-------

64/1, 64/2, 64/3	0.041
------------------	-------

65	0.158
----	-------

34	0.229
----	-------

33	0.241
----	-------

61/1, 61/2	0.013
------------	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 2.144

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 2.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 982-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—अमराडाड़ी

(घ) क्षेत्रफल —0.066 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ—निजी पट्टे की भूमि

2	0.060
---	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.060

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1	0.006
---	-------

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.006

अ+ब का योग : 0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 984-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—रघुराजगढ़

(घ) क्षेत्रफल —9.518 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ—निजी पट्टे की भूमि

1149	0.485
------	-------



(1)	(2)	(1)	(2)
1145	0.153	621/1, 621/2,	
1148	0.394	621/3, 621/4	0.866
1147	0.366	624	0.175
1146	0.366	625	0.023
1256	0.743	626	0.001
1196	0.042	615/1	
1255	0.072	615/2	
1207	0.051	615/3	
1209	0.063	615/4	0.829
1210	0.170	615/5	
1208	0.390	615/6	
704/1, 704/2	1.002	615/7	
1212	0.029	599	0.143
1249	0.005	598	0.288
1213	0.035	600/1, 600/2	0.186
1214	0.012	604	0.475
1215	0.079	605	0.333
1216/1, 1216/2	0.098	606	0.056
1218	0.158	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 9.485	
1219	0.041	<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
698	0.066	669	0.028
1220	0.008	1191	0.005
699/1, 699/2,		म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.033	
699/3, 699/4	0.386	अ+ब का योग : 9.518	
700/1, 700/2,		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
700/3, 700/4	0.027	मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस	
697/1		पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
697/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं	
697/3		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया	
697/4	0.005	जा सकता है.	
697/5		प. क्र. 986-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को	
697/6		इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
697/7		(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
701	0.338	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	
696/1, 696/2, 696/3		अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया	
696/4, 696/5, 696/6,	0.254	जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन	
696/7		हेतु आवश्यकता है:—	
620/1, 620/2, 620/3	0.216	<b>अनुसूची</b>	
622/1		(1) भूमि का वर्णन—	
622/2		(क) जिला—रीवा	
622/3		(ख) तहसील—मऊगंज	
622/4	0.056		
622/5			
622/6			
622/7			

(ग) ग्राम—सरई कृष्णकुमार  
(घ) क्षेत्रफल —3.758 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

206/1, 206/2, 0.132

206/3, 206/4

205 0.026

204/1/क

204/1/ख

204/1/ग 0.566

204/2

204/3

203/1

203/2

203/3 0.009

203/4

203/5

202/1/क

202/1/ख दुमट II

202/1/ग

202/1/घ

202/1/ङ 0.384

202/1/च

202/2/ख

202/2/ग

202/क

200/1, 200/2 0.138

199/1

199/2 0.327

199/2/क

198/1, 198/2 0.036

197/1

197/2 0.044

197/3

197/4

175/1

175/2 0.597

175/3

175/4

142 0.170

143/1, 143/2 0.161

148 0.161

(1) (2)

147/1

147/2 0.154

147/3/क

147/3/ख

146/1, 146/2 0.031

15 0.091

16 0.036

17 0.202

18/1, 18/2 0.304

18/3/क, 18/3/ख

201 0.019

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.588

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1 0.027

207 0.018

218 0.089

219/218 0.036

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.170

अ+ब का योग : 3.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 988-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—खुरहा

(घ) क्षेत्रफल —4.770 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)  
अ—निजी पट्टे की भूमि

102/1, 102/2 | 0.002

102/3, 102/4 |

144 0.015

136/1, 136/2, 136/3 0.990

135/1, 135/2 0.062

137 0.001

131/1, 131/2 0.045

134 0.053

132 0.056

103/1, 103/2 0.122

133 0.212

106 0.108

118 0.196

107 0.278

117/1, 117/2 0.050

108/1, 108/2 0.090

116/1, 116/2 0.019

110 0.270

112/1, 112/2 0.069

111/1, 111/2 0.335

30 0.034

31 0.155

34 0.264

32 0.012

33 0.432

25 0.336

24 0.253

23 0.265

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.724

ब—म. प्र. शासन की भूमि

109 0.046

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.046

अ+ब का योग : 4.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 990-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पतेला पुड़हन

(घ) क्षेत्रफल —1.549 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

65 0.392

64 0.001

63 0.057

62 0.282

67/1, 67/2 0.007

43 0.002

58/1

58/2

58/3 0.091

58/4

58/5

57/1, 57/2, 57/3 0.151

56 0.032

59 0.103

60 0.055

61 0.002

54 0.212

53 0.103

52 0.059

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.549

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 1.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 992-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—दुरौंध  
(घ) क्षेत्रफल —2.319 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/1	
1/2	
1/3	
1/4	0.700
1/5	
1/6	
2	0.081
4	0.503
5/1, 5/2	0.114
6	0.429
7	0.338
11/1, 11/2	0.004
8	0.150
अ. निजी भूमि का योग : 2.319	

### ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000  
अ+ब का योग : 2.319

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 994-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—अमवा  
(घ) क्षेत्रफल —10.035 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
160	0.353
217/1, 217/2	0.160
218/1, 218/2	0.573
212/1, 212/2	0.926
211/1, 211/2	0.046
210/1, 210/2	0.700
209/1, 209/2	0.022
208/1, 208/2, 208/3	0.884
205/1, 205/2	0.218
203/1	
203/1/1	0.087
203/2	
203/3	
292	0.083
298	0.038
295	0.302
297	0.040
296	0.500
434/1, 434/2	0.202
433	0.325

(1)	(2)
428	0.204
432/1, 432/2	0.001
439/1, 439/2	0.001
426	0.007
427	0.013
442/1, 442/2	0.249
443	0.017
444	0.224
445	0.034
447	0.233
448	0.032
449	0.023
450	0.027
396	0.090
395	0.020
394	0.122
397	0.033
398	0.009
400	0.027
403	0.063
401	0.108
390	0.019
404	0.439
351	0.334
352/1, 352/2	0.495
363	0.007
358	0.100
360	0.006
359	0.066
355	0.049
357	0.683
356	0.022
399	0.154
अ. निजी की भूमि का योग :	<u>9.370</u>

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

124	0.052
293	0.360
294	0.190
207	0.063

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.665अ+ब का योग : 10.035

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 996-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—कोठी  
(घ) क्षेत्रफल—3.365 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

**अ—निजी पट्टे की भूमि**

8	0.013
9	0.009
10	0.261
11	0.018
12	0.360
16/1, 16/2	0.783
13/1, 13/2	0.080
17/1, 17/2	0.445
18	0.039
19/1, 19/2	0.227
20	0.011
21	0.315
24	0.150
25/1, 25/2	0.172
26/1, 26/2, 26/3	0.362
22	0.063
23	0.057

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.365**ब—म. प्र. शासन की भूमि**योग : 0.000अ+ब का योग : 3.365

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 998-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—उलही खुर्द

(घ) क्षेत्रफल—6.610 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

14	0.211
15	0.072
27/1, 27/2	1.491
25	0.265
26	0.002
24	0.065
56	0.592
58/1, 58/2	0.518
82	0.013
81/1, 81/2	0.658
80	0.500

63/1

63/2

63/3

63/4

63/5

63/6

63/7

63/8

63/9

63/10

63/11

63/12

63/13

63/14

0.423

(1)

(2)

63/15

63/16

63/17

63/18

63/19

63/20

63/21

63/22

63/23

63/24

63/25

63/26

63/27

63/28

63/29

63/30

63/31

63/32

63/33

63/34

63/35

63/36

63/37

63/38

63/39

63/40

63/41

63/42

63/43

63/44

63/45

63/46

79

0.133

72

0.005

71

0.040

68

0.002

67

0.053

66/1

66/1/

66/2

1.440

66/3

70

0.008

69

0.119

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 6.610

ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग :	0.000
अ+ब का योग :	6.610
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
प. क्र. 1000-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—भोथी

(घ) क्षेत्रफल—4.577 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

## अ—निजी पट्टे की भूमि

99 0.200

98 0.024

175 0.022

101 0.150

100 0.052

97 0.035

95 0.100

103 0.040

102 0.022

94 0.184

105 0.026

90 0.041

91 0.022

93 0.053

87/1, 87/2 0.160

110 0.073

109/1, 109/2 0.030

(1)

(2)

111

0.090

112

0.091

142

0.016

108/1, 108/2

0.113

143

0.055

115

0.045

116

0.066

141

0.400

146

0.015

140

0.090

137

0.019

136

0.385

257/1, 257/2

0.035

256/1, 256/2

0.342

258

0.092

255

0.072

254

0.062

261

0.280

260/1, 260/2

0.203

262

0.101

263

0.065

271/1, 271/2, 271/3

0.011

270/1, 270/2

0.045

269

0.047

264

0.058

265

0.046

327

0.110

326

0.201

328

0.160

92

0.028

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.577

## ब—म. प्र. शासन की भूमि

योग : 0.000

अ+ब का योग : 4.577

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1002-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—अटरा

(घ) क्षेत्रफल—4.018 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

241/2/क/2	
241/2/क/1	
241/5	
241/2/ख	0.557
241/2/ग	
241/1	
241/4	
241/3	
270/1/ख, 270/1/क, 270/2	0.052
271/1/ख, 271/क, 271/2	0.353
272/1/ख, 272/1/क,	0.033
272/2, 272/3	
232/1, 232/2	0.216
277/2	0.033
277/1	
278/2, 278/1	0.115
279/1, 279/2	0.128
203/3	
203/5	
203/4	
203/1/क/1	0.411
203/1/क/2	
203/2	
204/1, 204/2, 203/3	0.196
200	0.062
197 शा. न. 198	0.132

(1)	(2)
199/1, 199/2, 199/3	0.199
196	0.065
195/3, 195/2, 195/1	0.086
194 शामिल नं. 193	0.404
150/1, 150/3, 150/2	0.141
148/2, 148/1	0.187
147	0.106
144	0.148
143	0.068
142/2, 142/1, 142/3	0.154
81/2, 81/1/क, 81/1/ख	0.068
80/3, 80/2, 80/1	0.028
74/5	
74/7	
74/8	
74/6	
74/1	0.035
74/2	
74/3	
74/4	
72	0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.979

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

280 0.039

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.039

अ+ब का योग : 4.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 5 अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची



के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—बुढ़ार  
(ग) ग्राम—बकहो, पटवारी ह. नं. 134  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1387	0.292
योग . .	0.292

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 78 से प्रभावित ग्राम बकहो रकबा 0.292 हे. निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2014

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 323-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना

- (ग) ग्राम—अर्दलाखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.00 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.13
61	0.12
226/2	0.44
192/1	0.18
210/1	0.13
योग . .	1.00

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 321-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—जामलीराजगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.00 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.14
26	0.09
27	0.04
28	0.04
29	0.01
34	0.60
90	0.03
98/1	0.144

(1)	(2)
98/1/1	0.006
98/3	0.01
104	0.22
105	0.13
106	0.22
107	0.07
192	0.40
195	0.67
196	0.30
197	1.00
201/2	3.00
277	0.47
276	0.36
275	0.85
274/1	0.13
209	0.60
218	0.20
219	0.24
220	0.58
221	1.08
229	0.30
231	0.10
253/1	3.38
254	0.34
252/1	3.21
241/1	0.40
252/2	2.27
179/1	0.20
217	0.14
224/1	0.03

कुल योग . . 22.00

उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—दीवाल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.14 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
62	0.14
कुल योग . .	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 324-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पंधाना  
(ग) ग्राम—राशोलाखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.62 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206	0.62
कुल योग . .	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 322-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14-नस्ती क्र. -एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—नावली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
534	0.18
535	0.18
522	0.20
433	0.21
516	0.20
472	0.16
306/3	0.10
443	0.05
444	0.06
कुल योग . . 1.34	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-नस्ती क्र. -एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद

- (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—सहेजला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.72 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
66/4	0.54
66/2	0.15
105	0.35
63	0.19
61	0.33
51/1	1.36
165/7	0.50
165/6	0.20
111/1	1.00
112	0.30
29	0.12
27/1	0.40
41/1	1.14
42/1	0.64
121/2	0.50
59/1	1.00
64	0.15
33/1	0.30
74/1	0.30
74/2	0.15
75/1	0.10
कुल योग . . 9.72	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्र. 6156-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—खिलचीपुर  
(ग) ग्राम—भूमरिया, विनायकबे  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.531 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
<b>ग्राम-भूमरिया क्षेत्रफल 2.289 हेक्टेयर</b>	
440/1/1	0.405
440/1/2	0.404
442/2/1	0.140
441/665	0.479
442/1/1	0.026
442/1/2	0.026
440/2	0.809
योग.	2.289
<b>ग्राम-विनायकबे क्षेत्रफल 0.242 हेक्टेयर</b>	
137	0.242
योग	0.242
महायोग	2.531

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—(भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि) के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. क / भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 9-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—बंडा  
(ग) ग्राम—खजरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.190 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97/2	1.000
111/2	0.050
112/2	0.140
योग	1.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2014-प्र. क्र. 10-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—बंडा  
(ग) ग्राम—बमाना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.010
136/4	0.170
2/4	0.590
136/5	0.240
योग . .	<u>1.010</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 11-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—बंडा

- (ग) ग्राम—ओडाहो  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.830 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129/4	0.400
129/5	0.430
योग . .	<u>0.830</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 12-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—बंडा  
(ग) ग्राम—पगरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.880 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
356	0.880
योग . .	<u>0.880</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 14-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

क्र. क/भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 13-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—शाहगढ़
- (ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/134	0.550
योग . .	
	<u>0.550</u>

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—शाहगढ़
- (ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.790 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
313	1.790
योग . .	
	<u>1.790</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री,

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा, एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 15th July 2014

No. 840-Confdl.-2014-II-2-1-2014.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Advance Course for Additional District Judges (promoted in the year 2014) from 1st to 7th August 2014** in the Academy, Additional District Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

#### Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1st August 2014 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance, i.e. latest by 3rd week on July, 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Advance course :—
  - (i) Judgment in Sessions case (contested)
  - (ii) Judgment in Civil Suit (contested)
  - (iii) Judgment in regular Civil Appeal
  - (iv) Judgment in Criminal Appeal
  - (v) Order in Criminal Appeal
  - (vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case.
5. The participant may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by Fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court.

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles.

9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. C-2978-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 19 मई से 2 जून 2014 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2980-दो-3-420-80 भाग-दस.—श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 173 दिवस (एक सौ तिहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. श्री शिव नारायण खरे, : 2-12-1985  
सेवानिवृत्त, (जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुंब न्यायालय, रीवा का  
नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-6-2014
3. नियुक्ति दिनांक 2-12-1985 : 1 वर्ष 3 माह  
से दिनांक 9-3-87 तक  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 3 माह  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित :  $1 \times 15 = 15$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण अवकाश  
की पात्रता (एक वर्ष में 15  
दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि :  $26 = 13 \times 15 = 195$   
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता  $1 \times 7 = 7$  दिन.  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर  
से तथा दो वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 217 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 44 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 173 दिन  
अवकाश समर्पण की  
पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. C-2982-दो-2-19-2007.—श्री आर. पी. वर्मा, तत्कालीन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



## संशोधित आदेश

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्र. B-3914-दो-2-20-2006.—श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके आवेदन-पत्र दिनांक 3 जुलाई 2014 के निवेदन अनुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-2651, दिनांक 24 जून 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि को संशोधित करते हुए ब्लाक वर्ष 2011 से 2013 तक की अवधि के लिए 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-3918-दो-2-37-2005.—श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4524-दो-2-61-2011.—श्री ए. के. पाण्डे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-4526-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत

किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. C-4048-दो-3-51-2003.—श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4050-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. C-4052-दो-2-49-2007.—श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 16 से 19 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरिराज किशोर शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4054-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 जून 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4060-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 से 30 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4062-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 17 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4064-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-4068-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4070-दो-2-20-2005.—श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 31 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4072-दो-3-47-2003.—श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 जून 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4074-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4076-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 1 से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2014

क्र. 843-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राकेश कुमार (गुप्ता), सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 07, विद्युत अधिनियम, 2003, इन्दौर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 868-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(1)	(2)	(3)
1	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. 904-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(1)	(2)	(3)
1	श्री सभापति यादव, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्र. 980-गोपनीय-2014-II-2-33-57 (Pt.-11).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय

के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री श्रीराम शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर.
2	कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. D-4654-दो-2-53-2011.— श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 26th July 2014

No. B-3825-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Vaibhav Mandloi, Presiding Officer of the Court of IIIrd Additional Sessions Judge Burhanpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter, Burhanpur.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी-3951-तीन-10-42-75 (शहडोल-बुधर).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल अपने घोषित कार्यस्थल शहडोल के अतिरिक्त, बुधर में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3951-III-10-42-75 (Shahdol-Budhar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Upendra Kumar Sonkar, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Shahdol in addition to his place of sitting declared at Shahdol, shall also sit at Budhar for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court there.

क्र. बी-3953-तीन-10-42-75 (सागर-बण्डा).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर अपने घोषित कार्यस्थल सागर के अतिरिक्त, बण्डा में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3953-III-10-42-75 (Sagar-Banda).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Yogesh Kumar Gupta, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Sagar in addition to his place of sitting declared at Sagar, shall also sit at Banda for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court there.

क्र. बी-3955-तीन-10-42-75 (मण्डला-निवास).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल मण्डला के अतिरिक्त, निवास में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3955-III-10-42-75 (Mandla-Niwas).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Virendra Kumar Pandey, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Mandla in addition to his place of sitting declared at Mandla, shall also sit at Niwas for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3957-तीन-10-42-75 (छिन्दवाड़ा-सौसर).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री जोसेफ माईकल राव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा अपने घोषित कार्यस्थल छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त, सौसर में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3957-III-10-42-75 (Chhindwara-Sausar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Joseph Michel Rao, AJ to Ist Addl. Distt. & Session Judge, Chhindwara in addition to his place of sitting declared at Chhindwara, shall also sit at Sausar for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3959-तीन-10-42-75 (सिवनी-लखनादौन).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी अपने घोषित कार्यस्थल सिवनी के अतिरिक्त, लखनादौन में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3959-III-10-42-75 (Seoni-Lakhnadon).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the

Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Sanjay Krishna Joshi, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Seoni in addition to his place of sitting declared at Seoni, shall also sit at Lakhnadon for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3961-तीन-10-42-75 (नीमच-जावद).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री हेमन्त जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच अपने घोषित कार्यस्थल नीमच के अतिरिक्त, जावद में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3961-III-10-42-75 (Neemuch-Javad).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Hemant Joshi, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Neemuch in addition to his place of sitting declared at Neemuch, shall also sit at Javad for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 872-गोपनीय-2014-दो-3-83-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी रूपाली भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती रूपाली उइके” पत्नी श्री पुष्परजसिंह उइके करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. 947-गोपनीय-2014-दो-3-86-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी मंजूषा इडपाचे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती मंजूषा तेकाम” पत्नी श्री सुमित तेकाम करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. 997-गोपनीय-2014-दो-3-87-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी शुभांगी पालो, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जबलपुर के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती शुभांगी पालो दत्त” पत्नी श्री निशान्त दत्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी-3936-पेंशन-चार-9-4-39-भाग-तीन-डी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2015 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	वर्ष 2015 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर.-एक-चार, दिनांक 16-4-76 के अनुसार.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>प्रथम श्रेणी अधिकारी</b>				
1	श्री एच. बी. खेडकर	लेखा अधिकारी, उ.न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	5-3-1955	31-3-15 अप.
2	श्री एस. के. साहा	रजिस्ट्रार, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	5-4-1955	30-4-15 अप.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>द्वितीय श्रेणी अधिकारी</b>				
1	श्री हरी ओम शिवहरे	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	8-2-1955	28-2-15 अप.
2	श्री रामसखा तिवारी	अनु. अधि., उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	12-2-1955	28-2-15 अप.
3	श्री निजाम उल्ला खान	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	22-2-1955	28-2-15 अप.
4	श्री आर. के. जौहरी	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.	24-6-1955	30-6-15 अप.
5	कुमारी शोभा पवार	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	6-7-1955	31-7-15 अप.
6	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	ग्रंथपाल, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	2-12-1955	31-12-15 अप.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 950-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

#### सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री विवेक सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बड़वाहा, जिला मण्डलेश्वर.	बड़वाहा	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्र. 926-गोपनीय-2014-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (1) (अनुपूरक सूची क्रमांक 01) दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम

के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014

क्र. B-3821-तीन-6-4-81भाग-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1753-तीन-6-4-81 भाग-5, दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

### अनुसूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	राजस्व जिला पन्ना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना का न्यायालय

No. B-3821-III-6-4-81-Pt.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1753-III-6-4-81 Pt. VI, dated 9th April 2013, namely:—

### AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification, in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted:—

### SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Devendra Prasad Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Panna.	Revenue District Panna	Court of Ist Additional Sessions Judge, Panna.



क्र. B-3823-तीन-6-4-81 पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-1751, दिनांक 9 अप्रैल 2014 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

### अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में) (2)	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम (4)
1	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.	बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

No. B-3823-III-6-4-81-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, by making slight amendments in its previous Notification No. D/1751 dated 9 April 2013 hereby appoints the following Additional Sessions Judge, Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :—

### SCHEDULE

No. (1)	Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)	Area for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)	Name of the Special Court established by the State Government (4)
1	Shri Umesh Kumar Shrivastava, XIIth Additional Sessions Judge Gwalior.	All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.	Court of XIIth Additional Sessions Judge, Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. B-3988-तीन-6-2-2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260(1)(ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

### सारणी

क्र. (1)	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
1	श्रीमती दुर्गा डुडवे (सोलंकी) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	कुक्षी	धार
2	कु. विनीता भटनागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	खरगौन	प.नि. मण्डलेश्वर
3	श्री शिवचरण पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	खरगौन	प.नि. मण्डलेश्वर
4	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	कसरावद	प.नि. मण्डलेश्वर

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री अरविंद दारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	भीकनगांव	प.नि. मण्डलेश्वर
6	श्रीमती सुमन उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
7	कु. मंजुषा इडपाचे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
8	श्री ए. के. दंदेलिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सौसर	छिन्दवाड़ा
9	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा
10	श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
11	श्री मयंक कुमार शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
12	श्री राहुल वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
13	श्री सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
14	कु. मधुलिका मूले, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
15	कु. सोनल पस्तारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
16	कु. प्रीति जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
17	श्री निशीथ खरे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सांवेर	इन्दौर
18	श्रीमती ज्योत्सना आर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सांवेर	इन्दौर
19	कु. सपना कौशल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	मऊ	इन्दौर
20	श्री राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	हातोद	इन्दौर
21	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छतरपुर	छतरपुर
22	श्री उमेश कुमार पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सिंगरौली	सिंगरौली
23	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सिंगरौली	सिंगरौली
24	श्री मनीष अनुरागी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	रतलाम	रतलाम

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई.)

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. 208-स्था.सैट-2014.—श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक कुल नौ दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री चतुर्वेदी जी को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री चतुर्वेदी जी को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते। अतः अवधि दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिए गिनी जावेगी।

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.